उत्तराखंड विधान सभा

प्रथम सत्र 2026

12 मार्च, 2026

[शिक्षा मंत्रालय - स्वास्थ्य मंत्रालय].

कुल प्रश्न 19

जनपद देहरादून के हर्रावाला स्थित सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल की स्वीकृति निर्माण व्यय एवं संचालन पी.पी.पी. मोड के संबंध में जानकारी।

*1 **श्री बृजभूषण गैरोला (डोईवाला):**

स्वास्थ्य मंत्रालय क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के हर्रावाला (देहरादून), में कैंसर की गम्भीर बीमारी के मरीजों के लिए सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल के भवन का निर्माण काफी पहले हो चुका है? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि हर्रावाला स्थित कैंसर अस्पताल की स्वीकृति कब हुई थी और अस्पताल के भवन निर्माण में कुल कितनी धनराशि व्यय हुई है? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त कैंसर अस्पताल को सरकार पी.पी.पी. मोड़ पर दिये जाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो उक्त अस्पताल का संचालन कब से प्रारम्भ हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के हर्रावाला (देहरादून), में कैंसर की गम्भीर बीमारी के मरीजों के लिए सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल के भवन का निर्माण काफी पहले हो चुका है? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि हर्रावाला स्थित कैंसर अस्पताल की स्वीकृति कब हुई थी और अस्पताल के भवन निर्माण में कुल कितनी धनराशि व्यय हुई है? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त कैंसर अस्पताल को सरकार पी.पी.पी. मोड़ पर दिये जाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो उक्त अस्पताल का संचालन कब से प्रारम्भ हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवक्ता एवं एल टी पदों की रिक्तियों एवं नियुक्ति के संबंध में।

***2** **श्री बृजभूषण गैरोला (डोईवाला):**

शिक्षा मंत्रालय क्या विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक) मंत्री अवगत हैं कि राज्य के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवक्ता एवं एल0टी0 के कई पद वर्षों से रिक्त होने के कारण छात्र-छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है? क्या यह सत्य है कि राज्य में सेंटर आॅफ एक्सीलेंस के रुप में अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोले गये थे? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवक्ता व एल0टी0 के कितने पद स्वीकृत हंै तथा कितने पद रिक्त हंै? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवक्ता व एल0टी0 शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

राज्य कर्मियों एवं पेंशनरों हेतु गोल्डन कार्ड योजना के अंतर्गत कैशलेस चिकित्सा सुविधा के क्रियान्वयन एवं लंबित देयों के भुगतान के संबंध में।

***3** **श्री विरेन्द्र कुमार (झबरेड़ा):**

स्वास्थ्य मंत्रालय क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य कर्मियों तथा पेन्शनरों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से लागू 'गोल्डन कार्ड' योजना के क्रियान्वयन में हो रही लापरवाही के फलस्वरुप राज्य सरकार के कर्मी कैशलेस इलाज की सुविधा के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भटकने को मजबूर हो रहे हंै? क्या यह भी सत्य है कि राज्य की राजधानी के प्रमुख चिकित्सालय जो राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध हैं, अपने लम्बित् देयकों का प्राधिकरण द्वारा भुगतान न किये जाने के कारण उक्त चिकित्सालयों द्वारा राज्य के कैशलेस इलाज की सुविधा देने से मना किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार गोल्डन कार्ड योजना के अन्तर्गत कैशलैस उपचार पुनः प्रारम्भ किये जाने हेतु तत्काल कोई कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

जनपद पिथौरागढ़ स्थित चिकित्सालय भवनों में भू-धंसाव निर्माण गुणवत्ता एवं सुरक्षा उपायों के संबंध में।

***4** **श्री मयूख सिंह महर (पिथौरागढ़):**

स्वास्थ्य मंत्रालय क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ में निर्माणाधीन/निर्मित चिकित्सालय के भवनों में भू-धंसाव के कारण जमीन दरक रही है और भवनों में दरारें आ रही हंै, जिससे चिकित्सालय में उपचार करा रहे मरीजों तथा कार्यरत कर्मचारियों के लिए खतरा बना हुआ है? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि चिकित्सालय भवनों के निर्माण से पूर्व भूमि की भू-वैज्ञानिकों से जाँच करायी

गयी थी? यदि हां, तो क्या विभाग उक्त के सम्बन्ध मे कोई जिम्मेदारी निर्धारित करेगा तथा सरकार द्वारा चिकित्सा भवनों के भू-धंसाव से सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हंै? यदि नहीं, तो क्यों?

प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट मिस ब्रांडिंग के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही खाद्य सुरक्षा सूचकांक में स्थिति सैंपलिंग कार्रवाई विवरण एवं एफडीए में रिक्त पदों तथा देहरादून में नई परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना के संबंध में।

*5 **श्री बृजभूषण गैरोला (डोईवाला):**

शिक्षा मंत्रालय क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग) मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट एवं मिस ब्रांडिंग के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या यह सत्य है कि उत्तराखण्ड खाद्य सुरक्षा सूचकांक में अत्यधिक निचले स्तर पर है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि पिछले 02 वर्षों में कितने खाद्य पदार्थों के सैंपल लिये गये तथा खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला में कितने सैंपल फेल हुए हैं एवं कितने कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है? क्या यह भी सत्य है कि उत्तराखण्ड में एफडीए में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षाधिकारी के कई पद रिक्त हंै? क्या सरकार द्वारा देहरादून में नई टैस्ंिटग लैब बनाने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो वह कार्यवाही क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

प्रदेश के जिला चिकित्सालयों विशेषकर यमुनोत्री विधान सभा क्षेत्र बड़कोट एवं चिन्यालीसौड़ में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी एवं चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के संबंध में।

*6 **श्री संजय डोभाल (यमुनोत्री):**

स्वास्थ्य मंत्रालय क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के प्रत्येक जिलों के स्थानीय अस्पतालों में अच्छे चिकित्सकों की कमी और बेहतर उपचार मशीनरी न होने के कारण स्थानीय जनता को प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि जिला उत्तरकाशी के यमुनोत्री विधान सभा क्षेत्र के बड़कोट एवं चिन्यालीसौड़ स्वास्थ्य केन्द्र में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के कारण मरीजों को हायर सेण्टर रेफर किया जाता है? क्या सरकार प्रदेश के प्रत्येक जिले के साथ-साथ यमुनोत्री विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में भी विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति कर बदहाल चिकित्सा व्यवस्था को सुधारेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

विद्यालयी शिक्षा माध्यमिक विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं विगत् 04 वर्षों में लाभार्थियों एवं व्यय विवरण तथा योजनाओं के प्रभावी संचालन हेतु कार्ययोजना के संबंध में।

*7 **श्री सुरेश गढ़िया (कपकोट):**

शिक्षा मंत्रालय क्या विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक) मंत्री बताने का कष्ट करंेगे कि विभाग द्वारा छात्रों के प्रोत्साहन हेतु कौन-कौन सी छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित की गई है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि विगत् 04 वर्षों मंे छात्रवृत्ति योजनाओं के द्वारा कितने छात्र-छात्राओं को कितनी धनराशि आवंटित की जा चुकी है? क्या सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजनाओं के संचालन में आ रही कठिनाईयों एवं योजनाओं के सफल संचालन हेतु कोई ठोस कार्ययोजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर अंतर्गत भाऊवाला में राजकीय चिकित्सालय स्थापना के संबंध में।

***8 श्री सहदेव सिंह पुण्डीर (सहसपुर):**

स्वास्थ्य मंत्रालय क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद देहरादून की विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत भाऊवाला में वर्तमान तक कोई भी सरकारी अस्पताल की सुविधा नहीं है? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि भाऊवाला क्षेत्र में शिक्षण संस्थान/कॉलेज/विद्यालय अधिक होने के कारण यहां आबादी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण स्थानीय निवासियों को उपचार हेतु 20-25 किमी0 की दूरी तय कर दूर-दराज स्थित अस्पतालों मंे जाना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के भाऊवाला में राजकीय चिकित्सालय खोलने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

प्रदेश के चिकित्सालयों में क्रय की गई अल्ट्रासाउंड एवं एम.आर.आई. मशीनों तथा रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति की स्थिति के संबंध में।

***9 श्री विनोद कण्डारी (देयप्रयाग):**

स्वास्थ्य मंत्रालय क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों हेतु कितनी अल्ट्रासाउण्ड एवं एम.आर.आई. मशीने क्रय की गयी तथा उसके सापेक्ष कितने रेडियालॉजिस्ट नियुक्त किये गये हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि क्रय की गयी मशीनों के सापेक्ष रेडियालॉजिस्ट नियुक्त हंै? यदि हां, तो क्या मंत्री जी तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखंेगे? यदि नहीं, तो क्यों?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विद्यालयों के क्लस्टरीकरण विलय की प्रगति के संबंध में।

***10 श्री सुमित हृदयेश (हल्द्वानी):**

शिक्षा मंत्रालय क्या विद्यालयी शिक्षा (बेसिक) मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राष्ट्रीय

शिक्षा नीति, 2020 के अन्तर्गत प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता एवं संसाधनों को बेहत्तर बनाने के लिए सरकारी स्कूलों का क्लस्टर बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस प्रक्रिया के अन्तर्गत कितने विद्यालयों का आतिथि तक विलय हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

प्रदेश में आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों उपचारित लाभार्थियों एवं लंबित भुगतान की स्थिति के संबंध में।

***11 श्रीमती ममता राकेश (भगवानपुर):**

स्वास्थ्य मंत्रालय क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में लागू आयुष्मान स्वास्थ्य योजना प्रदेश के किन-किन प्राइवेट/सरकारी अस्पतालों में लागू है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के कितने अस्पतालों द्वारा आयुष्मान कार्ड धारकों का उपचार किया गया तथा उक्त सभी अस्पतालों का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है? क्या यह भी सत्य है कि कुछ अस्पतालों का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा जिन अस्पतालों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, उनका अवशेष भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

जनपद बागेश्वर के विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों एवं नियुक्ति की कार्यवाही के संबंध में।

***12 श्रीमती पार्वती दास (बागेश्वर):**

शिक्षा मंत्रालय क्या विद्यालयी शिक्षा (बेसिक/माध्यमिक) मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर में ऐसे कितने राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय जूनियर हाईस्कूल, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राजकीय इण्टर कॉलेज हंै, जिनमें शिक्षकों की कमी है? क्या मंत्री जी इस बात से भी अवगत हैं कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी होने के कारण छात्र-छात्राओं को जिन विषयों के शिक्षक विद्यालयों में नहीं हैं, उन विषयों के अध्ययन का लाभ नहीं मिल पा रहा है? क्या सरकार छात्र-छात्राओं के हितों के दृष्टिगत राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय जूनियर हाईस्कूल, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

गोल्डन कार्ड योजना अंतर्गत पैथोलॉजी एवं रेडियोलॉजिकल जांच दरों में कटौती एवं दरों की समीक्षा के संबंध में।

***13 श्रीमती ममता राकेश (भगवानपुर):**

स्वास्थ्य मंत्रालय क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि गोल्डन कार्ड योजनान्तर्गत राज्य कर्मियों एवं पेन्शनधारकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के देयकों की

स्वीकृति के दौरान पैथोलाजी अथवा रेडियालॉजिकल जॉचों के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों में किये गये व्यय की दरों में कटौती की जा रही है? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है? क्या मंत्री जी सूचीबद्ध अस्पतालों की जांच की ऊॅची दरें और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दरों में भिन्नता की समीक्षा कर, कोई समाधान निकालेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

नर्सिंग अधिकारी भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तन परीक्षा आधारित चयन प्रणाली एवं अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट प्रदान किये जाने के संबंध में।

*14 **श्री भुवन चंद्र कापड़ी (खटीमा):**

स्वास्थ्य मंत्रालय क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि नर्सिंग भर्ती परीक्षा हेतु जारी विज्ञप्ति से बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी आक्रोशित और आन्दोलनरत हंै? यदि हां, तो पूर्व मंे लागू वर्षवार भर्ती की प्रक्रिया के स्थान पर परीक्षा आधारित नई प्रक्रिया लागू किये जाने के क्या कारण हैंे और पूर्व में लागू प्रक्रिया में क्या दोष हैं? क्या मंत्री जी बेरोजगार नर्सिंग अधिकारियों के हित के दृष्टिगत पूर्व से लागू वर्षवार भर्ती की प्रक्रिया को लागू करेंगे तथा आयु सीमा पूर्ण कर चुके अभ्यर्थियों को पूर्व भर्ती के वर्ष से अब तक के वर्ष में आयु सीमा में छूट प्रदान करेंगे? यदि नहीं, तो इसमें तकनीकी एवं व्यवहारिक कठिनाईयां क्या हंै?

जनपद पिथौरागढ़ स्थित गंगोत्री गर्ब्याल कन्या इंटर कॉलेज की स्थापना विकास कार्यों आधारभूत सुविधाओं एवं स्वीकृत धनराशि के विवरण के संबंध में।

*15 **श्री मयूख सिंह महर (पिथौरागढ़):**

शिक्षा मंत्रालय क्या विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक) मंत्री अवगत करायेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ में स्थित गंगोत्री गब्र्याल कन्या इण्टर कॉलेज की स्थापना कब हुई थी तथा स्थापना वर्ष से आतिथि तक विभाग द्वारा विद्यालय के विस्तार एवं सुरक्षा हेतु क्या-क्या कार्य किये गये हंै? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त विद्यालय में अध्ययनरत् लगभग एक हजार से अधिक छात्राओं के लिए शौचालय की व्यवस्था एवं विद्यालय की चाहरदीवारी के निर्माण न होने के क्या कारण है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त विद्यालय के रख-रखाव हेतु कब-कब एवं कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है, का सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध करायेंगे? यदि नहीं तो क्यों?

प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों की संख्या एवं उनमें कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में।

*16 **श्री महेश जीना (सल्ट):**

शिक्षा मंत्रालय क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में संचालित

संस्कृत विद्यालयों की संख्या कितनी है एवं इन सस्कृत विद्यालयों मंे अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षा दी जा रही है? क्या सरकार संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षा अनिवार्य रुप से दिये जाने की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषय की मान्यता एवं कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में।

*17 **श्री सुमित हृदयेश (हल्द्वानी):**

शिक्षा मंत्रालय क्या विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक) मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में सरकार द्वारा समय-समय पर बड़ी संख्या में कम्प्यूटर स्थापित गये हैं, के सापेक्ष प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों को कम्प्यूटर विषय की मान्यता दी गयी है? यदि हां, तो वर्तमान में सरकार द्वारा कितने कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है? यदि नहीं, तो इतनी बड़ी संख्या में कम्प्यूटर लगाने का औचित्य क्या है? क्या सरकार प्रदेश के सभी विद्यालयों में कम्प्यूटर विषय को मान्यता प्रदान करते हुए कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के राजकीय इंटर कॉलेजों में वाणिज्य कॉमर्स विषय संचालित किये जाने के संबंध में।

*18 **श्री महेश जीना (सल्ट):**

शिक्षा मंत्रालय क्या विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक) मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत 12वीं तक एक भी विद्यालय में वाणिज्य (कॉमर्स) विषय नहीं है, जबकि वर्तमान में वाणिज्य (कॉमर्स) जैसे महत्वपूर्ण विषय का होना अत्यधिक आवश्यक है? क्या सरकार छात्र हितों को दृष्टिगत रखते हुए विधान सभा क्षेत्र सल्ट के राजकीय इण्टर कॉलेजों में वाणिज्य (कॉमर्स) विषय को अनिवार्य रुप से संचालित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य कर्मियों पेंशनरों हेतु दंत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति एवं निजी दंत चिकित्सालयों के सूचीबद्धीकरण के संबंध में।

*19 **काजी मौ0 निजामुदीन (मंगलौर):**

स्वास्थ्य मंत्रालय क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि स्वास्थ्य की सुरक्षा के क्रम मंे दन्त चिकित्सा प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है? यदि हां, तो राज्य कर्मियों/पेन्शनरों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के क्रम में दन्त चिकित्सा यथा रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ब्रिज, इम्प्लान्ट आदि चिकित्सा उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति का प्राविधान नहीं किए जाने के

क्या कारण हंै? क्या सरकार राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को राज्य के प्रत्येक जनपद मुख्यालय में उपरिवर्णित चिकित्सा उपचार की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु निजी दन्त चिकित्सालयों को सूचीबद्ध करने के निर्देश देगी? यदि नहीं, तो इसमें क्या कठिनाई है?